संब्योविव /भिवानी / 16-85/1987.—चूंकि हरियाणा के राज्यपाल की राय है कि मैंब महा प्रवन्धक कन्फ्रेन्ड कार्यालय चण्डीगढ़, के श्रमिक श्री रणधीर सिंह तथा उसके प्रवन्धकों के मध्य इसमें इसके बाद लिखित मामलेमें कोई ग्रौद्योगिक विवाद है:— ग्रीर चूंकि हरियाणा के राज्यपाल विवाद को न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना बांछनीय समझते हैं।

इसलिए अब औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947, की धारा 10की उपधारा (1) के खण्ड (ग) द्वारा प्रैदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा सरकारी अधिसूचना सं 9641-1-अम-78-32574 दिनांक 6 नवम्बर 1970, के साथ गठित सरकारी अधिसुचना की धारा 7 के अधीन गठित श्रम न्यायालय, अम्बाला, को विवाद प्रस्त या उससे सम्बन्धित नीचे लिया मामला न्यायनिर्णय एक पंचाट तीन मास में देने हेतु निर्दिष्ट करते हैं, जो कि उक्त प्रवन्धकों तथा श्रमिक के वीच या तो विवाद प्रस्त मामला है या विवाद से सुसंगत अथवा सम्बन्धित मामला है :---

क्या श्री रणधीर सिह पुत्र श्री किश्वन लील की सेवाग्रों का समापन न्यायोचित तथा ठीक है ? यदि नहीं,तो वह किस राहत का हकदार है ?

सं श्रो०वि०/जी०जी०एन/45-85/1994 — चूंकि हरियाणा के राज्यपाल की राय है कि मैं० ए२०के० बैलवैटस, प्लाट नं० 11 पालम गुडगांवा रोड, गुडगांवा के श्रीमक श्री जोस जैकब तथा उसके प्रबत्धकों के मध्य इसमें इसके बाद लिखित मामले में कोई श्रीदोगिक विवाद है;

भौर चूंकि हरियाणा के राज्यपाल विवाद को न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना वांछनीय समझते हैं;

इसलिए, अब, औशीगिक विवाद अधिनियम, 1947, की धारा 10 की उपधारा (1) के खण्ड (ग) द्वारा प्रदान की गई शिक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा सरकारी अधिसूचना सं 5415-3-अम-68/15254, दिनांक 20 जून, 1978, के साथ पढ़ते हुए अधिसचना सं 11495-जी-अम- 57/11245, दिनांक 7 फरवरी, 1958, द्वारा उक्त अधिसूचना की धारा 7 के अधीन गठित अम न्यायालय, करीदाबाद, को विवादप्रस्त या उससे सुसंगत या उससे सम्बन्धित नीचे लिखा मामला न्यायिनगर्य एवं पंचाट तीन मास में देने हेतु निर्दिष्ट करते हैं को कि उक्त प्रवन्धकों तथा श्रमिक के बीच या तो विवादप्रस्त मामला है या विवाद से सुसंगत अथवा संबंधित मामला है :---

क्या. श्रो जोस जैकब की सेवाग्रों का समापन न्यायोचित तथा ठीक है? यदि नहीं, तो किस राहत का हकदार है?

सं ग्रो॰िव /प्रम्याला / 184-85 / 2001 — चूंकि हरियाणा के राज्यपाल की राय है कि मैं ॰ इण्डियन वेकलाईट प्रोडेक्टस, इण्डिस्ट्रीयल एरिया अन्याला शहर, के श्रामिक श्री साधु राम तथा उत्तके प्रबन्धकों के मध्य इसमें इसके बाद लिखित मामले में कोई ग्रीद्योगिक विवाद है ;

ग्रौर चूंकि हरियाणा के राज्यपाल विवाद को न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना वांछनीय समझते हैं;

े इसलिए, अब, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947, की घारा 10 की उपधारा (1) के खण्ड (ग) द्वारा प्रदान की गई शिक्तयों का प्रयोग करते हुए हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा सरकारी अधिसूचना सं० 3(44)84-3-श्रम, दिनांक-18 अप्रैल, 1984, द्वारा उक्त अधिनियम की घारा 7 के अधीन गठित श्रम न्यायालय, अम्बाला, को विवादग्रस्त या उससे सम्बन्धित नीचे लिखा मामला न्यायनिर्णय एवं पंचाट तीन मास में देने हेतु निर्दिष्ट करते हैं जो कि उक्त प्रवन्धकों तथा श्रमिक के बीच या तो विवाद प्रस्त मामला है या उससे सुसंगत अथवा सम्बन्धित मामला है :—

क्या श्री साधु राम, पुत श्री मंगत राम की सेवाग्रों का समापन न्यायोजित तथा ठीक है? यदि नहीं, तो वह किस राहत का हकदार है?

सं ग्रो वि । एफ.डी. | 251-85 | 200 7.--चूकि हरियाणा के राज्यपाल की राय है कि मैं जनन्तुर इण्डस्ट्रीज, प्रालि., प्लाट नं 270, सैक्टर 24, फरीदाबाद, के श्रीमक श्री चन्द्र भान तथा उसके प्रबन्धकों के मध्य इसमें इसके बाद लिखित मामले में कोई ग्रीदोगिक विवाद है;

भ्रोर चूंकि हरियाणा के राज्यपाल विवाद को न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना वांछनीय समझते हैं;

इसलिए, प्रब, ग्रौद्योगिक विवाद ग्रिधिनियम, 1947, को. धारा 10 की उर-घारा (1) के खण्ड (ग) द्वारा प्रदान की गई, शिक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपान इसके द्वारा सरकारी ग्रिधिसूचना सं 5415-3-भन-68/15254, दिनांक 20 जून, 1978, के साथ पढ़ते हुए ग्रिधिसूचना सं 11495-जी-श्रम-57/11245, दिनांक 7 फरवरी, 1958, द्वारा उक्त प्रिष्टसूचना की घारा 7 के प्रजीन गठित श्रम न्यायालय, फरोदाबाद, की विवादपस्त या उससे सुसंगत या उससे सम्बन्धित नीने लिखा मामला म्यायिनिर्णय एवं पंचाट तीन मास में दने हेतु निर्दिष्ट करते हैं जो कि उक्त प्रबन्धकों तथा श्रमिक के बीच या तो विवादपस्त मामला है या विवाद से सुसंगत ग्रयवा संबंधित मामला है :--

क्या श्री चन्द्र भान की सेवाग्रों का समापन न्यायोचित तथा ठीक है ? यदि नहीं, तो वह किस राहत का हकदार है ?